# आयातित शराब पर एक्साइज डयूटी घटाने का निर्णय वापस हो

**नई दिल्ली,** 13 दिसंबर (देशबन्धु)। द कंफैडरेशन आफॅ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज, सीआईएबीसी, ने महाराष्ट्र सरकार के उप—मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि आयातित शराब पर एक्साइज डयूटी घटाने के निर्णय को त्वरित आधार पर वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर यह सुविधा भारतीय शराब को भी प्रदान की जाए। सीआईएबीसी ने कहा है कि विदेश से आने वाली शराब पर एक्साइज डयूटी में इस तरह की भारी कमी से भारतीय शराब उद्योग तबाह हो जाएगा। इससे भारतीय और विदेश शराब उत्पादकों के बीच समान अवसर नहीं रहेगा। विदेशी शराब कंपनियां इससे लाभांवित होंगी। जबकि भारतीय शराब उद्धोग पर इसका नकारात्मक असर होगा। पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वह भारत में निर्मित उत्पाद को बढ़ावा दे। जो परंपरागत रूप से राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग देता रहा है। सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा कि विदेशी शराब को एक्साइज डयूटी में इस तरह भारी छूट देना भारतीय उद्योग को बर्बाद करना होगा। यह समान अवसर उपलब्ध कराने के नियम के खिलाफ भी है। यह संभव है कि जब यह निर्णय किया जा रहा होगा। उस समय सरकार को इससे संबंधित समुचित और वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हो कि यह कैसे भारतीय कंपनियों को बर्बाद करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल रोजगार पर प्रतिकूल असर होगा। साथ ही एमएसएमइ सेक्टर और भारतीय किसानों पर भी इसका बड़ा नकारात्मक असर होगा।